उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक विविधआवेदन संख्या. 2019 का 1392

राम कुमार और एक अन्य

याचिकाकर्ताओं....

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

.प्रतिवादी.....

उपस्थित :- सुश्री प्रभा नैथानी, अधिवक्ता, अधिवक्ताकर्ताओं के अधिवक्ता श्री अविदित नोलियाल की संक्षिप्त जानकारी रखते हुए। श्री S.K. चौधरी, D.A.G. उत्तराखंड राज्य की संक्षिप्त धारक सुश्री गीता परिहार के साथ।श्री संजय कुमार, निजी प्रतिवादी नं.2.

निर्णय

माननीय नयायमुर्ति श्री रविन्द्र मैथानी, (मौखिक)

इस याचिका में चुनौती मामला संख्या 13.06.2019 में पारित आदेश है। 2018 का 05, राज्य बनाम राम कुमार और अन्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 145 (संक्षेप में 'संहिता') के से उप-मंडल मजिस्ट्रेट, ऋषिकेश के न्यायालय द्वारा (संक्षेप में 'मामला') के साथ-साथ आदेश दिनांक 10.07.2019 को आपराधिक संशोधन सं। 2019 का 138, राम कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य को जिला और सत्र न्यायाधीश, देहरादून के न्यायालय द्वारा पारित किया गया (संक्षेप में 'संशोधन')।दिनांक 13.06.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा, संहिता की खंड 146 (1) के से एक आदेश पारित किया गया है और विवाद में सम्पति कुर्क की गई है।इस आदेश को संशोधन में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता के वकील को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. याचिकाकर्ता की ओर से, विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता विवाद में सम्पति के कब्जे में हैं।उन्हें कभी भी मामले का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए, कुर्की आदेश कानून की नजर में बुरा है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से नं।2, यह तर्क दिया जाता है कि सम्पति उसकी है, वह इसकी मालिक है; उसने परिसर में ताला लगा दिया था, लेकिन, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था।प्रतिवादी सं. द्वारा किए गए कुछ आवेदनों का संदर्भ दिया गया है।2.

5. प्रतिवादी सं।3 और 4 का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें सेवा दी गई है।

6. राज्य की ओर से, विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि आक्षेपित आदेश में दर्ज निष्कर्ष विरोधाभासी हैं क्योंकि एक ओर, याचिकाकर्ताओं का कब्जा दर्ज किया गया है और दूसरी ओर, कुर्की आदेश पारित किया गया है और निष्कर्ष कानून के अनुसार नहीं है।

7. मामले की कार्यवाही संहिता की धारा 145 के से कार्रवाई खंड उत्पन्न होती है।संहिता की धारा 145 अचल सम्पति के बारे में विवादों खंड संबंधित है और जब यह विवाद संभवतः शांति भंग करने का कारण बन सकता है, तो संहिता की धारा 145 की उप-धारा 1 में कार्यकारी मजिस्ट्रेट खंड किसी सम्पति पर अपने-अपने दावे करने के लिए एक विशिष्ट तिथि और समय पर पक्षों को बुलाने की अपेक्षा की गई है, जिसके संबंध में शांति भंग होने की आशंका मौजूद है।यह न्यायालय संहिता की धारा 145 को पुनः प्रस्तुत करने खंड रोकता है, लेकिन तत्काल याचिका के प्रयोजन के लिए संहिता की धारा 146 की उप-धारा 1 को उद्धृत करना पर्याप्त होगा, जो इस प्रकार हैः

"146 -विवाद के विषय को संलग्न करने और प्राप्तकर्ता नियुक्त करने की शक्ति।- (1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 145 खंड उपधारा (1) से आदेश करने के पश्चात् किसी समय मामले को आपात-स्थिति का मामला समझता है, या यदि वह यह निर्णय लेता है कि तब कोई भी पक्षकार ऐसे कब्जे में नहीं था, जैसा कि धारा 145 में निर्दिष्ट है, या यदि वह स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से कौन विवाद के विषय के ऐसे कब्जे में था, तो वह विवाद के विषय को तब तक संलग्न कर सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण न कर लेः

बशर्ते कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अब विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।

8. संहिता खंड खंड 146 खंड उप-खंड 1 का केवल अवलोकन संहिता खंड योजना को बहुत स्पष्ट करता है।सामान्य सेिस्थितियों में, यदि किसी सम्पति के संबंध में शांति भंग होने की आशंका होती है, तो पक्षों खंड संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने और अपने-अपने दावे करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन संहिता की धारा 146 की उप-धारा 1 को ध्यान में रखते हुए, यदि मजिस्ट्रेट धारा 145 (1) के से आदेश पारित करने के पश्चात मामले को आपातकालीन मानता है, या यदि वह निर्णय लेता है कि कोई भी पक्ष उस समय ऐखंड कब्जे में नहीं था, तो वह एक कुर्की आदेश पारित कर सकता है जब तक कि एक सक्षम अदालत उसके कब्जे के लिए हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं करती है।

9. याचिकाकर्ता की ओर से पानी के कनेक्शन से संबंधित कुछ तस्वीरें और दस्तावेज उनके कब्जे को दिखाने के लिए दायर किए गए हैं।न्यायालय प्रतिवादी के लिए वैध वकील से जानना चाहता था।2 वास्तव में किस तिथि को विवादग्रस्त सम्पति से उनका ताला खोला गया था।प्रतिवादी की ओर से नं.2, उनके जवाबी शपथ पत्र के लिए संलग्नक 1 का उल्लेख किया गया है जो प्रतिवादी सं।2 उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, ऋषिकेश को, जिस पर 08.12.2017 को समर्थन किया गया था, और इस दस्तावेज़ में ही, प्रतिवादी नं।2 ने कहा था कि उसने सम्पति पर ताला लगा दिया था।इसका मतलब है कि प्रतिवादी का ताला नं।2 दिसंबर, 2017 के महीने में भी वहाँ नहीं

था।अदालत ने प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अग्रेतर यह बताने का अनुरोध किया कि ताला कब खोला गया था, इसका कोई जवाब नहीं था।

10. दूसरी ओर, दिनांक 13.06.2019 के आक्षेपित आदेश में प्रतिवादी नं.2.यह तब प्रतिवादी नं की ओर से तर्क दिया गया था।2 कि याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण सम्पति की प्रकृति को बदला जा सकता है, इसका अर्थ है कि जिस दिन 13.06.2019 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, उसे प्रतिवादी नं।2 कि वह विवाद में सम्पति के कब्जे में नहीं थी।अब, दो बातें स्पष्ट हैं।प्रतिवादी नं. 1 के जवाबी शपथ पत्र के संलग्नक 1 के अनुसार।2, वह दिसंबर, 2017 के महीने में विवाद में सम्पति के कब्जे में नहीं था और जब 13.06.2019 को विवादित आदेश पारित किया गया था, तो यह प्रतिवादी नं।2 कि याचिकाकर्ताओं के पास भूमि का अधिकार था।जैसा कि कहा गया है, प्रतिवादी नं।2 न्यायालय को यह नहीं बता सका कि उसे कब बेदखल किया गया था या परिसर से उसके ताले कब तोड़े गए थे।

11. माथुरलाल बनाम भावरलाल और अन्य 1979 (4) एस. सी. सी. 665 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संहिता की धारा 145 और धारा 146 की योजनाओं पर चर्चा की और माननीय न्यायालय ने कहा कि दो स्थितियों के लिए प्रावधान जहां मजिस्ट्रेट यह तय करने में असमर्थ है कि कौन खंड पक्षकार कब्जे में थे या जहां उनका विचार है कि उनमें खंड कोई भी कब्जे में नहीं था, धारा 146 में बनाया गया है जिसके से वह विवाद के विषय को तब तक संलग्न कर सकता है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाता है।"।

12. अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 366 के मामले में, माननीय न्यायालय ने संहिता की खंड 146 (1) के दायरे पर चर्चा की और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

10. संहिता की धारा 145 (1) के से आदेश पारित करने के लिए आवश्यक सामग्री स्वचालित रूप खंड सम्पति की कुर्की के लिए आकर्षित नहीं होगी।

धारा 146 से तहत, मजिस्ट्रेट को कुर्की का आदेश पारित करने खंड पहले खुद को संतुष्ट करना होता है कि क्या आपातकाल मौजूद है। संहिता की धारा 146 के से आपात स्थिति के मामले को शांति भंग होने की आशंका के मामले खंड अलग किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को धारा 146 के से आदेश पारित करने खंड पहले उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी चाहिए कि वह इखंड आपातकाल का मामला क्यों समझता है।दूसरे शब्दों में, आपात स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलेख पर सामग्री होनी चाहिए जब पक्षों को प्रस्तुतीकरण किया जाता है, दस्तावेज प्रस्तुतीकरण किए जाते हैं या साक्ष्य प्रस्तुतीकरण किए जाते हैं।

11. हम इस मामले खंड पाते हैं प्रश्न यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है प्रश्न एक आपात स्थिति मौजूद है ताप्रश्न धारा 146 (1) को लागू प्रश्नया जा सके और संबंधित सम्पति को कुर्क प्रश्नया जा सके।संहिता की धारा 146 के अनुसार आपातकाल के मामले को शांति भंग होने की आशंका के मामले खंड अलग किया जाना चाहिए।जब रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि किसी एक पक्ष के पास अधिकार है,

सही या गलत, तो मजिस्ट्रेट आपातकाल के आधार पर कुर्की का आदेश पारित नहीं कर सकता है।आदेश इस तथ्य को स्वीकार करता है प्रश्न अशोक कुमार ने विचाराधीन सम्पति में निर्माण शुरू कर दिया है, इसलिए, सम्पति का कब्जा अपीलकर्ता अशोक कुमार के पास है, क्या यह कानूनी है या नहीं, यह निर्णय करने के लिए SDM पर नहीं है।

13. तत्काल मामले में, प्रतिवादी सं।2 स्वयं, याचिकाकर्ता विवाद में सम्पति के कब्जे में थे।ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट के पास संहिता की खंड 146 (1) के प्रावधान को लागू करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।इसलिए, सम्पति को कुर्क करने का आदेश कानून की नजर में गलत है और याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।लेकिन, साथ ही, याचिकाकर्ताओं को मामले में उपस्थित होने और अपने दावे करने का निर्देश दिया जा सकता है।

14.

याचिका की अनुमति है।

15. विवादित आदेशों को अपास्त दिया जाता है।हालाँकि, याचिकाकर्ता आज से एक महीने के भीतर मामले में पेश होंगे यद्यपि अपने दावे रखेंगे।इसके बाद नियुक्त मजिस्ट्रेट पक्षों को सुनने और कानून के अनुसार मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

(रवींद्र मैथानी, जे।) 05.08.2020

उज्जवल